

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021—कार्तिक 28, शक 1943

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, भा.प्र.से. (2013), अपर कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है।
5. श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूँकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,  
(अ) अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24” में संशोधन हेतु जारी अगिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 की दिनांक से अंकित संशोधन क्रमांक-20 (बीस) के द्वारा जोड़े गये परिशिष्ट-(6.22) राज्य में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु “औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज” के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रावधान, नियम एवं शर्तें लागू की जाती हैं :—

**औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज**

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेंगी :—

**( 6.22.1 ) ब्याज अनुदान :—** पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :—

उद्यम क्षेत्र की का श्रेणी		सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
स्तर		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सुक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	75	20	6	75	25	7	75	30
	ब	6	75	25	7	75	30	8	75	35
	स	7	75	40	8	75	50	9	75	55
	द	8	75	45	10	75	55	11	75	60
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	75	30	5	75	40	6	75	45
	ब	6	75	35	6	75	45	7	75	50
	स	7	75	45	8	75	60	9	75	65
	द	8	75	50	10	75	65	11	75	70

( 6.22.2 ) **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :—** पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा :—

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	40	40	45	80	45	90
	ब	40	50	45	90	45	100
	स	45	60	50	100	50	110
	द	45	70	50	110	50	120
मध्यम उद्योग	अ	35	80	40	90	40	100
	ब	40	90	45	100	45	110
	स	45	100	45	125	45	130
	द	45	120	45	130	50	140

**टीप :—**

- (1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं.
- (2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी.

( 6.22.3 ) **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :—** केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु.

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)
श्रेणी-अ परिशिष्ट-7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत.

(1)	(2)	(3)	(4)
श्रेणी-ब परिशिष्ट-7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत.
श्रेणी-स परिशिष्ट-7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत.
श्रेणी-द परिशिष्ट-7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत.

**टीप :-**

- (1) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात् वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिये मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी.
- (2) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी.

**( 6.22.4 )**

**विद्युत शुल्क छूट :-** पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित) के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शक्तीकरण प्रकरणों में विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :-

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)
श्रेणी-अ परिशिष्ट-7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(1)	(2)	(3)	(4)
श्रेणी-ब परिशिष्ट-7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-स परिशिष्ट-7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-द परिशिष्ट-7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.

**टीप :—** केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी.

( 6.22.5 ) **मंडी शुल्क से छूट :—** नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रु. 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

( 6.22.6 ) **अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत :—** औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट (6.10) में यथा प्रावधानित.

( 6.22.7 ) **परिवहन अनुदान :—** औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोड़कर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी. सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019-24 की समयावधि तक मिलेगी.

( 6.22.8 ) **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग ( निःशक्त ) रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान ( पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान ) :—** नीति के परिशिष्ट-6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा.

**टीप :—** उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगे.

( ब ) **अन्य कार्यकारी निर्देश :—**

(1) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई मूल अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी.

- (2) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित स्टाम्प ड्यूटी छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिककर (पंजीयन) विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।
- (3) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं के अनुरूप होगी।
- (4) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विद्युत शुल्क छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।
- (स) **स्वप्रेरणा से निर्णय :**— राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।
- (द) **कार्यकारी निर्देश :**— अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।
- (इ) नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (फ) इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।
- (ज) **योजना का क्रियान्वयन :**— योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

**गृह (सी-अनुभाग) विभाग**  
**(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2021

**विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2022 का सूचना तथा कार्यक्रम**

क्रमांक एफ-09-114/गृह-सी/परीक्षा/2021.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 24 जनवरी, 2022 से सोमवार 31 जनवरी, 2022 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अम्बिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

**सोमवार, दिनांक 24-01-2022**

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
<b>सोमवार, दिनांक 24-01-2022</b>		
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

**मंगलवार, दिनांक 25-01-2022**

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
<b>मंगलवार, दिनांक 25-01-2022</b>		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों की सहायता से), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	



## बुधवार, दिनांक 26-01-2022 को शासकीय अवकाश

(1)	(2)	(3)
गुरुवार, दिनांक 27-01-2022		
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	Paper-5, “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 27-01-2022		
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

**शुक्रवार, दिनांक 28-01-2022**

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 28-01-2022		
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शनिवार, दिनांक 29-01-2022		
45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
<b>शनिवार, दिनांक 29-01-2022</b>		
51.	प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
<b>रविवार, दिनांक 30-01-2022 को शासकीय अवकाश</b>		
<b>सोमवार, दिनांक 31-01-2022</b>		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

**नोट :-**

- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें। संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-12-2021 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण देव गौतम, सचिव।

### गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ-1-02/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अजय कुमार यादव (भा.पु.से.-2004)	पुलिस अधीक्षक जिला-रायपुर	उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर
2.	श्री बट्टीनारायण मीणा (भापुसे-2004)	उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर एवं चालू प्रभार पुलिस अधीक्षक जिला-जांजगीर-चांपा.	पुलिस अधीक्षक जिला-दुर्ग
3.	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.-2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग	पुलिस अधीक्षक जिला-रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव।

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 8 अक्टूबर 2021

प्ररूप-1

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2621/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	एकड़ में	हेक्टेयर में	(5)
बलरामपुर- रामानुजगंज	वाड्डफनगर	कोटराही	22.27	9.02	कोटराही जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई 28-10-2021 को समय 11.00 बजे (स्थान) पंचायत भवन कोटराही पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कोटराही जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	कुल 16 खातेदार/परिवार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	राशि 474.15 लाख (चार करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र.
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कोटराही जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण से 260 हे. खरीफ क्षेत्र में फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. कोटराही के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शाए गए तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 500000/- (पांच लाख रु. मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2021

रा.प्र.क्रमांक/06/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	मरेया	3.099	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	बटपरगा व्यपवर्तन योजना का वीयर एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2021

रा.प्र.क्रमांक/04/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	सितकालो	0.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	बटपरगा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2021

रा.प्र.क्रमांक/05/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	खोंधला	2.222	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	गेरवा नाला व्यपवर्तन योजना का वीयर एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	रोडोपाली	0.946	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) रायगढ़ संभाग, रायगढ़.	रोडोपाली – मुडागांव मार्ग चौड़ीकरण में ग्राम रोडोपाली का प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202009042100039/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छिंच प.ह.नं. 27	0.376	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202009042100040/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कराजोर प.ह.नं. 27	0.172	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.



रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202009042100041/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेतला प.ह.नं. 15	0.089	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत करीजोर माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202101042100100/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिंजिर प.ह.नं. 03	0.124	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केनसरा माईनर- 1 नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202101042100101/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केनसरा प.ह.नं. 15	0.413	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केनसरा माईनर- 1 नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भीम सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2021

क्रमांक/11572/अ-82/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242	0.012
244/1	0.016
731/1	0.202
731/2	0.049
243/1	0.049
280, 281	0.073
353, 353	0.024
284, 285, 807	0.109
247	0.008
योग	0.542

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भडेरियापारा, प.ह.नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.542 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शम्भू नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जितेन्द्र कुमार शुक्ला**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्रमांक/14/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा  
(ख) तहसील-लुण्ड्रा  
(ग) नगर/ग्राम-लमगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.463 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1479/2	0.616
1477	0.077
1479/3	0.296
1479/1	0.250
1480/1	0.283
1480/2	0.020
1481/2	0.380
1483/2	0.809
1483/3	0.607
1476	0.125
योग	3.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असकला-बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्रमांक/15/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा  
(ख) तहसील-लुण्ड्रा  
(ग) नगर/ग्राम-बुलगा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.288 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1462/2	0.044
1460/1	0.081
1459	0.064
1434/2	0.048
1463/3	0.048
1437	0.032
1434/1	0.048
1395	0.045
1397	0.153
1462/1	0.044
1396	0.115
1435	0.032
1460/2	0.062
1461/1	0.180
1398/2	0.032
1423	0.144
1432/4	0.088
1458	0.028
योग	1.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असकला-बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2021

(1)

(2)

क्रमांक/16/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-लुण्ड्रा

(ग) नगर/ग्राम-चोरकीडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.261 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

414/2

0.097

146/5

0.344

442

0.044

145/1

0.020

437

0.101

146/9

0.272

439

0.083

146/7

0.050

139/1

0.202

405/2

0.062

430

0.022

142/1

0.245

142/2

0.124

414/3

0.067

157/3

0.080

401/2

0.060

132/2

0.081

132/1

0.138

414/7

0.082

411/2

0.125

142/4

0.121

145/2

0.020

424

0.108

योग

6.261

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असकला-बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्रमांक/17/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा  
(ख) तहसील-लुण्ड्रा  
(ग) नगर/ग्राम-असकला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102	0.024
126/3	0.054
782/1	0.019
108/4	0.024
145/1	0.032
782/2	0.024
109	0.038
145/2	0.032
783	0.105
110	0.038
150	0.072
784/1	0.008
124	0.120
151/4	0.061
1339	0.048
126/1	0.084
778/1	0.092
1340	0.019
126/2	0.046
780/1	0.008
1341/1	0.129

योग

1.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असकला-बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्रमांक/18/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा  
(ख) तहसील-लुण्ड्रा  
(ग) नगर/ग्राम-जरहाडीह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.159 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1281	0.191
1254/44	0.300
1327/15	0.020
1389/1	0.060
1241/2	0.168
1021/1	0.298
1294	0.078
1327/21	0.230
1011	0.073
1362/3	0.096
1410/4	0.132
1289/1	0.051
1261/1	0.102
1010/2	0.172
1254/50	0.149
1026	0.040
1295	0.080
1017/5	0.132

(1)	(2)	(1)	(2)
1010/3	0.036	1121	0.012
1362/2	0.086	1335	0.056
1015/2	0.032	1001/1	0.016
1293	0.078	1328/5	0.070
1289/5	0.061	1031	0.064
1017/4	0.272	1119	0.074
1331	0.064	1389/2	0.133
1027	0.060	1260	0.037
1298	0.020	1254/46	0.120
1328/4	0.032	1384/3	0.020
1007/2	0.152	1327/14	0.018
1384/1	0.114	1254/58	0.162
1289/2	0.043	1122/1	0.093
1122/2	0.016	1039/2	0.074
1254/22	0.101	1277	0.023
1362/1	0.032	1280	0.197
1028	0.008	1259	0.116
1290	0.075	1349	0.072
1258/2	0.040		
1001/2	0.041	योग	6.159
1120	0.081		
1350	0.032	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असकला- बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.	
1337	0.032		
1327/5	0.118	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1366/1	0.120		
1029	0.040		
1388	0.232		
1261/2	0.222	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
1254/60	0.190		

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 21 सितम्बर 2021

क्रमांक/2526/प्र-1/अ.वि.अ./2021.—ग्राम एटमेटा को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में न्यायालय कलेक्टर, राजनांदगांव का राजस्व प्रकरण क्रमांक 2017040902000017/323 ब/121 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-09-2021 आदेश में कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 90, सहपठित धारा 73 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, ग्राम पंचायत बूचाटोला के अंतर्गत ग्राम एटमेटा को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है.

नवीन राजस्व ग्राम एटमेटा के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :—

1. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल — 99.374 हेक्टेयर
2. कुल आबादी भूमि — 2.104 हेक्टेयर

3. कुल जनसंख्या — 252
  - (1) महिला — 135
  - (2) पुरुष — 117
4. कुल परिवार — 40
5. शासकीय भवनों की संख्या — 05
  - (1) प्राथमिक शाला भवन — 01
  - (2) आंगनबाड़ी भवन — 01
  - (3) आदिवासी भवन — 01
  - (4) सार्वजनिक कला मंच — 02
6. ग्राम बूचाटोला से ग्राम एटमेटा की दूरी — 1 किमी

उपरोक्तानुसार जानकारी सादर सम्प्रेषित है.

रा.प्र.क्र. 2017040902000017/323 ब/121 वर्ष 2016-17

श्री बालसिंग व अन्य समस्त ग्रामवासी ग्राम एटमेटा तह. छुरिया — आवेदक  
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

छ.ग. शासन — अनावेदक

आदेश

( पारित दिनांक 06-09-2021 )

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/1562/675/2017/सात-1 नया रायपुर दिनांक 15-03-2017 के माध्यम से एवं ग्राम वासी ग्राम एटमेटा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर यह प्रकरण प्रारंभ किया गया. छ.ग. शासन से प्राप्त पत्र में आवेदक समस्त ग्रामवासी ग्राम एटमेटा तह. छुरिया द्वारा प्रस्तुत ग्राम एटमेटा ग्राम पंचायत बूचाटोला को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत आवेदन को मूलतः कार्यवाही हेतु भेजा गया. पुनः आवेदक बालसिंग अन्य ग्रामवासियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय छ.ग. शासन रायपुर के समक्ष दिनांक 25-11-2019 को तह. छुरिया द्वारा प्रस्तुत ग्राम एटमेटा ग्राम पंचायत बूचाटोला को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से टोकन क्रमांक 2500719018069 दिनांक 27-11-2019 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ. पुनः श्री बालसिंग एवं अन्य ग्रामवासियों ग्राम एटमेटा द्वारा छ.ग. शासन राजस्व विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम एटमेटा तहसील छुरिया को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवेदन पत्र छ.ग. शासन राजस्व विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

2. ग्रामवासियों द्वारा ग्राम एटमेटा ग्राम पंचायत बूचाटोला को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर जांच एवं प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार छुरिया को निर्देशित किया गया.

तहसीलदार छुरिया द्वारा जांच कर प्रतिवेदन/प्रकरण प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदित संबंध में उनके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया तथा विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया

उद्घोषणा पश्चात् नियत समयावधि तक किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ. ग्राम पंचायत बुचाटोला जिसके अंतर्गत एटमेटा है का ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार छुरिया के प्रारंभिक प्रतिवेदन पश्चात् पुनः विभिन्न बिन्दुओं पर तहसीलदार छुरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. तहसीलदार एवं अ.वि.अ. (रा) डोंगरगांव से प्राप्त प्रतिवेदनों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है :—

- i. ग्राम एटमेटा ग्राम पंचायत बुचाटोला प.ह.नं. 29 तह. छुरिया का आश्रित ग्राम है, जिसकी जनसंख्या 252 (महिला 135 पुरुष 117) है, ग्राम का कुल क्षेत्रफल 99.478 हे. है जिसमें से मकबूजा 80.542 हेक्टेयर गैर मकबूजा 16.832 हेक्टेयर आबादी 2.104 हे. तथा ग्राम में परिवारों की संख्या 40 खाता धारकों की संख्या 45 तथा शासकीय भवनों की संख्या 03 जिसमें प्राथमिक शाला भवन 01 आंगनबाड़ी 01 आदिवासी भवन 01 सार्वजनिक कला मंच 02 निस्तारी तालाब की संख्या 01 ग्राम बुचाटोला से ग्राम एटमेटा की दूरी 1 किलोमीटर है.

- ii. ग्राम एटमेटा वन ग्राम नहीं है वन विभाग द्वारा ग्राम एटमेटा को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में अनापत्ति दी गई है.
  - iii. ग्राम एटमेटा के मात्र नाम का उल्लेख बुचाटोला के नक्शा के उत्तर दिशा में मौजा एटमेटा का उल्लेख मिसल बन्दोबस्त में (1919-20) है किन्तु अभिलेखागार में अधिकार अभिलेख व अन्य राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है. एटमेटा का राजस्व अभिलेख राजस्व अभिलेख (खसरा बी-1 आदि) वर्ष 1977-78 से लगातार उपलब्ध है.
  - iv. ग्राम एटमेटा का राजस्व रिकार्ड उपलब्ध है जिसमें ग्राम में कुल खसरा 111 एवं कुल रकबा 238.15 एकड़/96.43 हेक्टेयर है. ग्राम एटमेटा में चरनोई हेतु शासकीय घास भूमि खसरा नं. 67 रकबा 0.551 हे. शमशान घाट हेतु शासकीय घास भूमि खसरा नं. 28 रकबा 0.154 हे. उपयोग किया जा रहा है.
  - v. अधिकार अभिलेख सन् 1963 ई. के अनुसार ग्राम बुचाटोला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 517.495 हे. है बी-1 सन् 1959-60 के अनुसार ग्राम बुचाटोला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 517.495 हे. है, बी-1, 1977-78 के अनुसार ग्राम एटमेटा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 99.374 हे. है. जिन्सवार में ग्राम बुचाटोला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 616.862 हे. है, स्पष्टतः जिन्सवार में ग्राम बुचाटोला का कुल क्षेत्रफल 517.495 हे. तथा एटमेटा का कुल 99.374 हे. सम्मिलित है. इस प्रकार से यदि ग्राम एटमेटा को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है तो इस स्थिति में ग्राम बुचाटोला तथा छुरिया के रकबे में बढ़ोतरी नहीं होगी.
3. प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WPC 2567/2020 पक्षकार थान सिंग नेताम व अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 05-11-2020 निम्नानुसार है :-

The grievance of the petitioner in the present writ petition is the inaction on the part of the respondent no. 2 in not declaring the Village Eatmeta panchayat buchatola Block and tahsil Churiya District Rajnandgaon as a revenue village under the provisions of Sections 73 and 90 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959. The counsel for the petitioner referred to various documents in this regard and where ultimately it has been directed that a decision has to be taken at the level of the Collector who is the competent authority for declaring the village as a revenue village.

2. Learned additional Advocate General at this juncture submits that since the application of the petitioner is already pending before the respondent no. 2 and also taking note of Annexure P6 and correspondence made by the Secretary of the State of Chhattisgarh dated 29-07-2019 let the writ Petition be Disposed of directing the Respondent No. 2 to take a decision at the earliest.
  3. Given the said submission by the counsel for the parties, this court is of the opinion that the writ petition need not be kept pending for long by admitting the same, the writ petition can be disposed off at the motion stage directing the respondent no. 2 to take a decision on the issue of desalaring the village. Eatmeta as a revenue village under the provisions of Chhattisgarh Land revenue Code 1959. It is expected that the respondent no. 2 shall take a decision at the earliest] preferably with in a period of sixty days from the date of receipt of the copy of this order.
  4. With the aforesaid direction, the present writ petition stands disposed off.
4. प्रकरण एवं अधिनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रकरण के तथ्यों का परिशीलन किया. प्रकरण में यह स्थापित तथ्य है कि ग्राम एटमेटा जो कि ग्राम पंचायत बुचाटोला का आश्रित ग्राम है, मिसल बंदोबस्त के समय से एटमेटा स्वतंत्र ग्राम रहा है जो बुचाटोला के मिशाल नक्शा (1919-20) के उत्तर में इन्द्राज सरहद मैजा एटमेटा से प्रमाणित है. किसी कारणवश वर्तमान में ग्राम एटमेटा राजस्व अभिलेख अधिकार अभिलेख निस्तार पत्रक व मिसल उपलब्ध नहीं है. ग्राम एटमेटा का राजस्व अभिलेख यथा खसरा बी-1 आदि वर्ष 1977-78 से वर्तमान में पटवारी के पास चालू नक्शा खसरा बी-1 उपलब्ध है. जो इसके स्वतंत्र ग्राम होने की पुष्टि करते हैं. इसे स्वतंत्र ग्राम घोषित किए जाने से कोई भी प्रभाव यथा राजस्व अभिलेखों, सीमाओं आदि के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह सब विशेषताएं पूर्व से ही ग्राम एटमेटा में विद्यमान है. ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा भी ग्राम एटमेटा को ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है.



5. इस संबंध में विधि के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 ग्रामों को विभाजित या संयोजित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की बंदोबस्त अधिकारी की शक्ति —

“बंदोबस्त अधिकारी इस संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समामेलित कर सकेगा, या किसी ग्राम की सीमाओं को उनमें किसी ऐसे ग्राम के जो उनके सामीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उनमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उनमें से अपर्जित करके, परिवर्तित कर सकेगा”.

**छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 ( य-5 ) के अनुसार** “ग्राम से अभिप्रेत है कोई ऐसा भू भाग जिसे इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी ऐसी विधि के, जो तत्समय प्रवृत्त है, उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था, तथा कोई ऐसा अन्य भू भाग जिसे किसी राजस्व सर्वेक्षण में एतद् पश्चात् ग्राम के रूप में मान्य किया जाए या जिसके राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करे”.

**धारा 90 के अनुसार** “राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान, कलेक्टर जबकि राज्य सरकार द्वारा उसे निर्देश दिया जाए, धारा 68, 69, 70, 72 तथा 73 के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा”.

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ 11-20/2018/सात-4 नया रायपुर दिनांक 29-07-2019 के द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-90 के सहपठित धारा-73 के अंतर्गत ग्राम एटमेटा तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव को राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां, जिला कलेक्टर को प्रदत्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. इस प्रकार से धारा 73 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु यह न्यायालय सक्षम है.

प्रकरण के अवलोकन तथा अधिनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपरोक्तानुसार विवेचना के पश्चात् छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 सहपठित धारा 73 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया ग्राम पंचायत बुचाटोला के अंतर्गत ग्राम “एटमेटा” को राजस्व ग्राम घोषित करता हूं इस संबंध में नियमानुसार अधिसूचना का प्रकाशन कराया जावे.

आज दिनांक 06-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,  
कलेक्टर.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर  
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/3143.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/2504 रायपुर दिनांक 22-07-2019 द्वारा श्री भूपेन्द्र जोशी, तहसीलदार तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक/क/वित्त-1/2021/3054 बिलासपुर दिनांक 12-08-2021 द्वारा श्री पेखन टोण्ड्रे, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री भूपेन्द्र जोशी, तहसीलदार तखतपुर के स्थान पर श्री पेखन टोण्ड्रे, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार तखतपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/3145.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/3454 रायपुर दिनांक 04-08-2018 द्वारा श्री जी. आर. जांगड़े वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जैजेपुर को कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

अपर कलेक्टर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/7594/स्थापना/2021 जांजगीर दिनांक 02-07-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर के भारसाधक अधिकारी श्री जी.आर.जांगड़े वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री एन. के. भारद्वाज अनुविभागीय अधिकारी कृषि जांजगीर को कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर के भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री जी. आर. जांगड़े वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जैजेपुर के स्थान पर श्री एन. के. भारद्वाज अनुविभागीय अधिकारी कृषि जांजगीर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

शिव अनंत तायल,  
संचालक.

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग  
डी.के.एस. अस्पताल के पास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2021

क्रमांक 3369(5)/मा.अ.आ./स्था./2021.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेश क्रमांक 8697/2389/21-ब/छ.ग./2021 दिनांक 18-08-2021, Endorsement No. 681/Confdl./2021/II-2-17/2001 (Pvt. IV) Bilaspur Dtd. 02-09-2021, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 6-4/2021/1-7 नवा रायपुर दिनांक 01-09-2021 आदेशों के परिपालन श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में (प्रतिनियुक्ति पर) संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 06-09-2021 को पूर्वान्ह कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

गिरिधारी नायक,  
कार्यवाहक अध्यक्ष.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1889.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे, श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी एवं तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, जिला-सूरजपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/05/2018, दिनांक 02 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

( के. सी. देवसेनापति )  
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## भारत निर्वाचन आयोग

### निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/05/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, जो छत्तीसगढ़ के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, द्वारा 28 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के पत्र सं. No. 250/निर्वा.सुप/छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 253/निर्वा.सुप./छ.वि.स.चु.-18/ईईएम/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-कल्याणपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़, 497229, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/05/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 05-Bhatgaon Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Surajpur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Surendra Lal Singh Neti, Communist Party of India (Marxist) contesting candidate from 05-Bhatgaon Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Surajpur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 4th March, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Surendra Lal Singh Neti, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th August, 2019 Sh. Surendra Lal Singh Neti, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Surendra Lal Singh Neti, on 28th August 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Surajpur vide his letter No. 250/निर्वा.सुप/छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 dated 22nd August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Surajpur vide his letter No. 253/Ele.Sup/CHLA-18/EEM/2020 dated 24th August, 2020, has stated that Sh. Surendra Lal Singh Neti, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Surendra Lal Singh Neti, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Surendra Lal Singh Neti, resident of Village-Kalyanpur, Post-Kalyanpur, Tah-Surajpur, District-Surajpur, Chhattisgarh 497229 and the contesting Communist Party of India (Marxist) candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 05-Bhatgaon Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/04/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, जो छत्तीसगढ़ के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, द्वारा 28 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के पत्र सं. No. 250/निर्वा.सुप/छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 253/निर्वा.सुप./छ.वि.स.चु.-18/ईईएम/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, ग्राम-मजीरा, पोस्ट-लटोरी, थाना-जयनगर, तहसील-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./—

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/05/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 05-Bhatgaon Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Surajpur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Tileshwar Prasad Rajwade, Independent contesting candidate from 05-Bhatgaon Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Surajpur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Tileshwar Prasad Rajwade, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th August, 2019 Sh. Tileshwar Prasad Rajwade, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Tileshwar Prasad Rajwade, on 28th August 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Surajpur vide his letter No. 250/निर्वा.सुप/छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 dated 22nd August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Surajpur vide his letter No. 253/Ele.Sup/CHLA-18/EEM/2020 dated 24th August, 2020, has stated that Sh. Tileshwar Prasad Rajwade, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Tileshwar Prasad Rajwade, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Tishwar Prasad Rajwade, resident of Village-Majira, Post-Latori, Thana-Jainagar, Tah-Surajpur, District-Surajpur, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 05-Bhatgaon Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

कार्यालय, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 12 नवम्बर 2021

शुद्धि पत्र

क्रमांक 1170/नगानि/कवर्धा/स्ट्रक्चरप्लान/बिरकोना/2021.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15(4) के तहत “बिरकोना निवेश क्षेत्र” का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकरण की सूचना क्रमांक-869/नगानि/कवर्धा स्ट्रक्चरप्लान बिरकोना/2021 कबीरधाम, दिनांक 22 जुलाई 2021 जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) के भाग-1, पृ.क्र.-861 में दिनांक 24 सितंबर 2021 को मुद्रित हुई है, में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना की अनुसूची “बिरकोना निवेश क्षेत्र की सीमाएं” एतद्वारा विलोपित करता है. शेष सूचना यथावत् रहेगी.

नवीन कुमार,  
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

क्रमांक/12318/वित्त-1/2021.—प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कोरबा जिला में पदस्थ निम्नांकित संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान में पदस्थ किया जाता है :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय (3)	नवीन पदस्थापना कार्यालय (4)
1.	श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं प्रोटोकाल अधिकारी कोरबा	जिला कार्यालय कोरबा
2.	श्री हरिशंकर पैकरा, डिप्टी कलेक्टर	जिला कार्यालय कोरबा	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं प्रोटोकाल अधिकारी कोरबा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

हस्ता./-  
कलेक्टर.



## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 01/L.G./2021/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 05-01-2021 to 08-01-2021 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 04 days from 26-06-2021 to 29-06-2021 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 09 days from 01-07-2021 to 09-07-2021 along with permission to remain out of headquarters from 01-07-2021 till before the National Lok Adalat on 10-07-2021 and earned leave for 02 days from 12-07-2021 to 13-07-2021 along with permission to remain out of headquarters from 11-07-2021 till before the Court hours of 14-07-2021.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 02/L.G./2021/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur), is hereby, granted earned leave for 06 days from 21-12-2020 to 26-12-2020 along with permission to remain out of headquarters from 20-12-2020 till before the office hours of 28-12-2020.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 03/L.G./2021/II-2-21/2006.—Shri Deepak Kumar Tiwari, the then Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 04 days from 05-10-2020 to 08-10-2020 and earned leave for 05 days from 07-12-2020 to 11-12-2020 along with permission to leave headquarters from 06-12-2020 to 13-12-2020.

During the period of commuted leave & earned leave, as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 600 days of half-pay-leave & 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 04/L.G./2021/II-2-38/2018.—Shri Shahabuddin Qureshi, I/c Registrar (Computerization)-cum-Central Project Co-ordinator, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 27-01-2021 to 30-01-2021 along with permission to leave headquarters from the second half of 26-01-2021 till the morning of 01-02-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 221 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 05/L.G./2021/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Registrar (I & E) & (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 06-04-2021 to 09-04-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 06/L.G./2021/II-3-46/2007.—Smt. Kiran Chaturvedi, Judge Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted child care leave for 61 days from 19-04-2021 to 18-06-2021 along with permission to remain out of headquarters from 17-04-2021 to 20-06-2021 and child care leave for 36 days from 27-07-2021 to 31-08-2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of child care leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Chaturvedi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 550 days of child care leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 07/L.G./2021/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 15 days from 27-04-2021 to 11-05-2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 08/L.G./2021/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Judge Family Court, Bemetara is hereby, granted commuted leave for 30 days from 28-05-2021 to 26-06-2021 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters from 19-05-2021 to 09-06-2021 and earned leave for 15 days from 27-06-2021 to 11-07-2021 in continuation of commuted leave.

During the period of commuted leave & earned leave as the case, may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 340 days of half-pay-leave & 238 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 09/L.G./2021/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, the then Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-01-2021 to 15-01-2021 along with permission to remain out of headquarters from 09-01-2021 to 15-01-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 235 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 10/L.G./2021/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 06 days from 27-03-2021 to 01-04-2021 along with permission to remain out of headquarters from 27-03-2021 to 02-04-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 11/L.G./2021/II-3-7/2008.—Smt. Vinita Warner, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 07 days from 24-12-2020 to 30-12-2020 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Warner, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 12/L.G./2021/II-2-5/2016.—Shri Hirendra Singh Tekam, Judge, Family Court, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 05 days from 14-06-2021 to 18-06-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 11-06-2021 to till before the Court hours of 21-06-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tekam, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 13/L.G./2021/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, the then Special Judge, under SC & ST (P.A.) Act, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 05 days from 27-10-2020 to 31-10-2020 along with permission to remain out of headquarters from 23-10-2020 to 01-11-2020, earned leave for 04 days from 23-06-2021 to 26-06-2021 along with permission to remain out of headquarters from 23-06-2021 to 27-06-2021 and earned leave for 07 days from 02-07-2021 to 08-07-2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 14/L.G./2021/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, Registrar (S & A), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 10 days from 27-10-2020 to 05-11-2020 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 205 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 15/L.G./2021/II-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 15-02-2021 to 17-02-2021 along with permission to remain out of headquarters from 13-02-2021 to 17-02-2021 and earned leave for 05 days from 05-07-2021 to 09-07-2021 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 16/L.G./2021/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 05 days from 22-12-2020 to 26-12-2020 along with permission to remain out of headquarters after the working hours of 21-12-2020 till the morning of 28-12-2020 and earned leave for 08 days from 23-04-2021 to 30-04-2021 along with permission to remain out of headquarters from 23-04-2021 to 27-04-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+14 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th August 2021

No. 17/L.G./2021/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi, the then Judge, Family Court, Dhamtari, is hereby, granted earned leave for 04 days from 27-01-2021 to 30-01-2021 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 27-01-2021 till 31-01-2021 and earned leave for 06 days from 19-07-2021 to 24-07-2021 along with permission to remain out of headquarters from 17-07-2021 to 25-07-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 201 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN.)

---